भारत सरकार
मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय
पशुपालन और डेयरी विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या- 672
दिनांक 03 फरवरी, 2026 के लिए प्रश्न

राष्ट्रीय पशुपालन बोर्ड

672. श्री देवेश शाक्यः

श्री बाबू सिंह कुशवाहाः

क्या **मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) राष्ट्रीय पशुपालन बोर्ड (एनएएचबी) की स्थापना के उद्देश्य तथा पशुपालकों की आय बढ़ाने, पशुधन उत्पादकता बढ़ाने, नस्लों में सुधार लाने तथा पशु स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत बनाने में इसकी वास्तविक भूमिका क्या है;

(ख) देश में तथा विशेषकर उत्तर प्रदेश में पशुपालकों के कल्याण हेतु सरकार एवं एनएएचबी द्वारा क्रियान्वित प्रमुख योजनाओं के अंतर्गत प्राप्त ठोस उपलब्धियों का ब्यौरा क्या है;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान उत्तर प्रदेश में पशुपालन एवं डेयरी विकास के लिए आवंटित, जारी तथा व्यय की गई धनराशि का ब्यौरा क्या है;

(घ) उक्त निधियों से एटा, कासगंज, आंवला (बरेली) एवं जौनपुर जैसे कृषि-प्रधान एवं पिछड़े जिलों में आरंभ की गई विशिष्ट परियोजनाओं, विकसित अवसंरचना तथा लाभार्थी-उन्मुख कार्यों का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) क्या इन जिलों में अपेक्षित प्रगति प्राप्त नहीं हो पाई है, यदि हाँ, तो इसके लिए उत्तरदायी एजेंसियाँ कौन-सी हैं तथा सरकार द्वारा बनाई गई समयबद्ध सुधारात्मक कार्ययोजना का ब्यौरा क्या है?

उत्तर
मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री
(श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह)

(क) राष्ट्रीय पशुपालन बोर्ड नामक कोई संगठन नहीं है।

(ख) उपरोक्त (क) में दिए गए उत्तर के आलोक में प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) उत्तर प्रदेश सरकार के पशुपालन विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार, वर्ष 2022-23 से वर्ष 2024-25 तक पिछले तीन वर्षों के दौरान उत्तर प्रदेश सरकार की 6657.38 करोड़ रुपये की मांग के मुकाबले 5757.76 करोड़ रुपये आवंटित किए गए थे। उत्तर प्रदेश सरकार ने वर्ष 2024-25 तक पिछले तीन वर्षों के दौरान सभी योजनाओं के अंतर्गत 5649.73 करोड़ रुपये (जारी बजट का 98.22%) का व्यय किया है।

(घ) राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के प्रयासों को अनुपूरित करने के लिए, भारत सरकार दिसंबर 2014 से देशी नस्लों के विकास और संरक्षण, बोवाइन आबादी के आनुवंशिक उन्नयन और दुग्ध उत्पादन एवं उत्पादकता बढ़ाने के लिए राष्ट्रीय गोकुल मिशन (RGM) लागू कर रही है, जिससे दुग्ध उत्पादन किसानों के लिए अधिक लाभकारी हो सके। देशी नस्लों

के विकास और संरक्षण, बोवाइन आबादी के आनुवंशिक उन्नयन के लिए RGM के तहत उठाए गए कदम, प्रदत्त सहायता और विभिन्न घटकों के तहत किसानों को प्राप्त लाभ निम्नलिखित हैं:

(i) देशी नस्लों के सांडों सहित उच्च गुणवत्ता वाले सांडों के सीमन का उपयोग करके राष्ट्रव्यापी कृत्रिम गर्भाधान कार्यक्रम (NAIP) का कार्यान्वयन। इस घटक के अंतर्गत, 50% से कम कृत्रिम गर्भाधान कवरेज वाले जिलों में किसानों के घर पर ही कृत्रिम गर्भाधान (AI) सेवाएं निःशुल्क प्रदान की जाती हैं। पिछले तीन वर्षों में उत्तर प्रदेश राज्य में 144.74 लाख पशुओं को कृत्रिम गर्भाधान के अंतर्गत कवर किया गया, 231.92 लाख कृत्रिम गर्भाधान किए गए और 80.29 लाख किसान लाभान्वित हुए। एटा, कासगंज, आंवला (बरेली) और जौनपुर जिलों में NAIP के अंतर्गत लाभान्वित किसानों का विवरण इस प्रकार है:

क्र सं	जिले का नाम	कृत्रिम गर्भाधान किए गए पशुओं की संख्या	किए गए कृत्रिम गर्भाधान की कुल संख्या	लाभान्वित किसानों की संख्या
1	एटा	225211	342103	121002
2	कासगंज	133686	219969	67761
3	बरेली	297500	473553	160248
4	जौनपुर	141504	201933	84785
कुल		797901	1237558	433796

(ii) पशुपालन और डेयरी विभाग ने सेक्स सॉर्टेड सीमन उत्पादन सुविधाएं स्थापित की हैं तथा सेक्स सॉर्टेड सीमन का उपयोग करके त्वरित नस्ल सुधार कार्यक्रम लागू कर रहा है, जिसका उद्देश्य 90% तक सटीकता के साथ बछड़ियों का उत्पादन करना है, जिससे दुधारू पशुओं की आबादी में वृद्धि हो, नस्ल में सुधार हो और किसानों की आय बढ़े।

(iii) उच्च आनुवंशिक गुणवत्ता वाले सांडों के उत्पादन हेतु संतति परीक्षण और वंशावली चयन कार्यान्वयन

(iv) इन-विट्रो फर्टिलाइजेशन (IVF) तकनीक का कार्यान्वयन: यह तकनीक एक ही पीढ़ी में गोपशुओं की आनुवंशिक गुणवत्ता में सुधार लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इसके अतिरिक्त, किसानों को उचित दरों पर तकनीक उपलब्ध कराने के लिए सरकार ने देशी IVF मीडिया लॉन्च किया है। देशी नस्लों के उत्कृष्ट पशुओं के प्रजनन हेतु विभाग ने उत्तर प्रदेश में एक IVF प्रयोगशाला स्थापित की है और 627 व्यवहार्य भ्रूणों का उत्पादन किया है, जिनमें से 505 भ्रूणों का स्थानांतरण किया गया और 126 बछड़ियां-बछड़े पैदा हुई हैं।

(v) ग्रामीण भारत में सामुदायिक संसाधन व्यक्तियों/बहुउद्देशीय कृत्रिम गर्भाधान तकनीशियनों (मैत्री) को किसानों के घर पर ही गुणवत्तापूर्ण कृत्रिम गर्भाधान सेवाएं प्रदान करने के लिए प्रशिक्षित और सुसज्जित किया जाता है। पिछले तीन वर्षों में उत्तर प्रदेश राज्य में 7300 मैत्री नियुक्त की गई हैं। पशुपालन और डेयरी विभाग ने पिछले तीन वर्षों में उत्तर प्रदेश सरकार को RGM के तहत 17313.43 लाख रुपये जारी किए हैं।

इसके अलावा, राष्ट्रीय डेयरी विकास कार्यक्रम (NPDD) योजना के तहत, उत्तर प्रदेश में 8 परियोजनाओं को अनुमोदित किया गया है, जिनकी कुल परियोजना लागत 9123.78 लाख रुपये है, जिसमें केंद्र सरकार का हिस्सा 7496.00 लाख

रुपये है। इन परियोजनाओं का कार्यान्वयन प्रादेशिक सहकारी डेयरी फेडरेशन PCDF) द्वारा किया जा रहा है। अब तक, उत्तर प्रदेश में डेयरी सहकारी समितियों के अवसंरचना के सुदृढीकरण/विकसित करने के लिए कार्यान्वयन एजेंसी को 5004.08 लाख रुपये की राशि दी जा चुकी है। अनुमोदन के बाद, 4 परियोजनाएं पूरी तरह से वापस ले ली गईं और 2 परियोजनाओं का आंशिक कार्यान्वयन राज्य सरकार द्वारा किया गया, जिसके परिणामस्वरूप 3707.27 लाख रुपये की राशि वापस कर दी गई।

डेयरी सहकारी समितियों और किसान उत्पादक संगठनों को सहायता कार्यक्रम (SDCFPO) के तहत 2 दूध संघों, लखनऊ दुग्ध संघ और वाराणसी दुग्ध संघ को दिए गए 51.50 करोड़ रुपये के कार्यशील पूंजी ऋण में से 21.65 लाख रुपये नियमित ब्याज सब्सिडी के रूप में जारी किए गए हैं। इसके बाद उत्तर प्रदेश से कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय पशुधन मिशन (NLM) के अंतर्गत पशुधन बीमा घटक के लिए 853 लाख रुपये की केंद्रीय राशि जारी की है, जिससे 5.22 लाख पशुओं का बीमा किया जाएगा। इसके अलावा, NLM योजना के उद्यमिता कार्यक्रम के तहत बरेली में 3.87 करोड़ रुपये की परियोजना लागत वाली छह परियोजनाएं और एटा में 0.88 करोड़ रुपये की परियोजना लागत वाली दो परियोजनाएं अनुमोदित की गई हैं, जिनके लिए संबंधित लाभार्थियों को क्रमशः 1.56 करोड़ रुपये और 0.42 करोड़ रुपये की सब्सिडी जारी की गई है।

पशुपालन अवसंरचना विकास निधि (AHIDF) के तहत 1629.25 करोड़ रुपये की परियोजना लागत के साथ कुल 36 परियोजनाओं को अनुमोदित किया गया है। विवरण इस प्रकार है:

क्रम सं	परियोजनाओं का विवरण	परियोजनाओं की संख्या	परियोजना लागत (करोड़ रु. में)
01	दूध प्रसंस्करण एवं मूल्यवर्धन	18	1168.63
02	पशु चारा संयंत्र	11	363.06
03	नस्ल वृद्धि फार्म	06	89.65
04	मांस प्रसंस्करण एवं मूल्यवर्धन	01	8.01

36 परियोजनाओं में से, एटा जिले में 29 करोड़ रुपये की परियोजना लागत वाली एक पशु चारा इकाई और बरेली जिले में 22.33 करोड़ रुपये की परियोजना लागत वाली दो पशु चारा इकाइयों को संस्वीकृति दी गई है। लाभार्थियों की मांग के आधार पर परियोजनाओं को अनुमोदित किया गया है।

पशुधन स्वास्थ्य एवं रोग नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत पिछले तीन वर्षों में 416.74 करोड़ रुपये की राशि संस्वीकृत और जारी की गई है। पशुधन स्वास्थ्य एवं रोग नियंत्रण कार्यक्रम के तहत 520 मोबाइल पशु चिकित्सा इकाइयों (MVU) के लिए सहायता प्रदान की गई थी और ये इकाइयां इन जिलों सहित वर्तमान में कार्यरत हैं।

(ङ) उपर्युक्त तथ्यों के आलोक में प्रश्न ही नहीं उठता।

*****